



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 18, 2017/आश्विन 26, 1939

No. 271]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017/ASVINA 26, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2017

सं. 32/2015-2020

विषय : अग्रिम प्राधिकार पत्रों को मिलाने (क्लबिंग), निर्यात दायित्व अवधि का विस्तार और औषधि के आयात-पूर्व शर्त के साथ अपंजीकृत स्रोतों से आयात हेतु जारी किए गए प्राधिकार पत्रों में वास्तविक चूक के मामलों के नियमितीकरण से संबंधित प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के अध्याय-4 में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/94/180/186/एम-18/पीसी-4.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार जनहित में प्रक्रिया पुस्तक, 2015-2020 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जो निम्नानुसार है:

1. प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.38 में संशोधन किया गया है जिसे इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

“4.38 प्राधिकार पत्रों को मिलाने (क्लबिंग) की सुविधा

- (i) 31 मार्च, 2009 को या इससे पहले जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के किसी क्लबिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ii) क्लबिंग हेतु अनुरोध एएनएफ-4ग में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, जिसने प्राधिकार पत्र जारी किया है, को करना होगा।
- (iii) अग्रिम प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की सुविधा ऐसे प्राधिकार पत्रों के मोचन/नियमितीकरण हेतु ही उपलब्ध होगी तथा आगे किसी आयात अथवा निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (iv) क्लबिंग की सुविधा उन अग्रिम प्राधिकार पत्रों के लिए वार्षिक आवश्यकताओं हेतु भी उपलब्ध होगी, जिन्हें विदेश व्यापार नीति 2009-14 और 2015-20 की अवधि के दौरान जारी किया गया है जहां कहीं निर्यात एवं आयात अधिसूचित मानक निविष्टि उत्पाद मानदंड (सिओन) के अनुसार हुआ हो।
- (v) केवल ऐसे प्राधिकार पत्र जिनके तहत सट्टा शुल्क छूट प्राप्त की गई है, को ही क्लबिंग की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे प्राधिकार पत्र अलग-अलग वित्तीय वर्ष के हो सकते हैं।

- (vi) किसी प्राधिकार पत्र के निर्यात दायित्व अवधि के बाहर किए जाने वाले निर्यात की स्थिति में निर्यात दायित्व अवधि के विस्तार की अनुमति संयोजन शुल्क के भुगतान पर प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.42 के अनुसार ऐसे प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग के पहले दी जा सकती है।
- (vii) केवल ऐसे अग्रिम प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की जाएगी जिनमें निर्यात सभी प्राधिकार पत्रों के तहत सबसे पहले जारी किए गए प्राधिकार पत्र की प्रारंभिक/विस्तारित निर्यात दायित्व अवधि के भीतर किए गए हैं।
- (viii) क्लबिंग केवल तभी अनुमत किया जाएगा जब पहले प्राधिकार पत्र में हुए निर्यात दायित्व की पूर्ति में कमी हो तथा बाद के प्राधिकार में अतिरिक्त निर्यात किया गया हो। तथापि, इस शर्त पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए जब प्राधिकार पत्रों की वैधता अवधि (आयात के लिए) साथ-साथ चलती हो और अनुवर्ती प्राधिकार पत्रों में किए गए आयात प्रथम प्राधिकार की वैधता अवधि (आयात के लिए) के भीतर हो तथा प्रथम प्राधिकार की वैधता अवधि के भीतर किया गया ऐसा आयात प्रथम प्राधिकार में किए गए निर्यात की सीमा तक यथानुपात आधार पर हो, समान हो या अत्यधिक हो। प्रथम प्राधिकार पत्र की वैधता के समाप्त होने के बाद जारी बाद के प्राधिकार पत्रों को क्लब करने की अनुमति नहीं होगी।
- (ix) विभिन्न निर्यात दायित्वों की अवधि के साथ जारी प्राधिकार पत्रों को क्लब करने की अनुमति होगी।
- (x) सबसे पहले जारी प्राधिकार पत्र के प्रारंभिक या विस्तारित निर्यात दायित्व की अवधि समाप्त होने के बाद किए गए निर्यात के लेखा जोखा पर ऐसे प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग के बाद निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- (xi) इनपुटों जो सभी प्राधिकार पत्रों में सामान्य हैं, को ही क्लब किया जाएगा तथा मानदंड समिति द्वारा सिओन/तदर्थ मानदंड के अनुसार शुल्क मुक्त इनपुटों की गणना की जाएगी। दूसरे शब्दों में सभी प्राधिकार पत्रों में शामिल सभी इनपुटों का समान होना आवश्यक नहीं है।
- (xii) निर्यात उत्पाद के लिए विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया में यथा निर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन क्लबिंग करने पर कायम रखना होगा। यदि क्लबिंग करने पर मूल्य या मात्रा में कमी का पता चलता है तो उसे प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.49 के प्रावधानों के तहत नियमित करना होगा।
- (xiii) क्लबिंग के बाद प्राधिकार पत्रों को सभी प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकार पत्र माना जाएगा। प्राधिकार पत्रों को क्लबिंग के बाद आंके गए कुल सीआईएफ मूल्य और कुल एफओबी के आधार पर मूल्य संवर्धन की गणना की जाएगी।
- (xiv) उन प्राधिकार पत्रों के मामले में किसी क्लबिंग की अनुमति नहीं होगी जिनमें क्षेत्रीय प्राधिकारी को किसी गलत जानकारी/जालसाजी का पता चलता है। इसके अलावा, उन मामलों में किसी क्लबिंग की अनुमति नहीं होगी जहां ईओडीसी/मोचन पत्र पहले ही जारी कर दिया गया है अथवा क्षेत्रीय प्राधिकारी/सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णयन आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।
- (xv) परिशिष्ट-30 क (विदेश व्यापार नीति 2009-14 के तहत जारी)/परिशिष्ट-4अ(विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत जारी) के तहत शामिल प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग के लिए अतिरिक्त प्रावधान और 18 महीनों से कम ईओपी के साथ जारी प्राधिकार पत्र:
 - a) क्लब किए गए प्राधिकार पत्रों की निर्यात दायित्व अवधि की गिनती क्लब किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी भी प्राधिकार पत्रों में सबसे पहले के आयात की तारीख से होगी।
 - b) ऐसे प्राधिकार पत्रों को क्लब करने की अनुमति होगी बशर्ते सभी निर्यात क्लब किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी भी प्राधिकार पत्रों में सबसे पहले के आयात की तारीख से आरंभिक/विस्तारित निर्यात दायित्व अवधि के भीतर पूरे हों।

2) पैरा 4.42(घ) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

- (घ) परिशिष्ट 4अ (विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत जारी) के अंतर्गत जारी प्राधिकार पत्रों हेतु निर्यात दायित्व अवधि को निर्धारित निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि की आधी से अधिक अवधि से बढ़ाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में संयोजन शुल्क अपूर्ण पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 0.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से लगाया जाएगा यदि किया गया निर्यात प्रारंभिक निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि के अंदर 50 प्रतिशत से अधिक है तथा प्रारंभिक निर्यात दायित्वपूरा करने की अवधि में 50 प्रतिशत से कम निर्यात किए जाने पर 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से शुल्क लगाया जाएगा।

3) पैरा 4.49 में सम्मिलित किया गया उप पैरा (छ):

(छ) ऐसे मामलों में, जहाँ आयात-पूर्व शर्त के साथ अपंजीकृत स्रोतों से औषधियों के आयात के लिए प्राधिकार पत्र जारी किया गया, वास्तविक चूक का नियमितीकरण।

आयात पूर्व शर्त के साथ अपंजीकृत स्रोतों के माध्यम से किए गए औषधियों के आयात का निम्नलिखित रूप से नियमितीकरण किया जाएगा:-

- (i) प्राधिकार-पत्र धारक मानदंडों के अनुसार आयातित मात्रा की पूरी खपत दर्शाते हुए दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा। यदि निर्यात दायित्व को पूरा करने में कमी रह जाती है तथा अप्रयुक्त आयातित मात्रा प्राधिकार-पत्र धारक के पास रह जाती है तो प्राधिकार पत्र धारक या तो अधिकार क्षेत्र वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें उनकी उपस्थिति में अप्रयुक्त आयातित मात्रा को नष्ट किए जाने को प्रमाणित किया जाएगा या प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के पैरा 4.43क के अनुसार उसी आपूर्तिकर्ता को इसका पुनः निर्यात किए जाने का प्रमाण होगा।
- (ii) निर्यात दायित्व अवधि समाप्त होने के पश्चात् औषधियों की अप्रयुक्त मात्रा का उपयोग करते हुए मुक्त पोत लदान बिलों/उसी प्राधिकार पत्र के तहत किए गए निर्यात को उपर्युक्त पैरा (i) में यथा उल्लिखित नाशन प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने की एवज में स्वीकृत किया जाएगा बशर्ते निर्यात किए गए औषध का सटीक वर्णन और तकनीकी विशेषताएं अग्रिम प्राधिकार पत्र में उल्लिखित निर्यात मदों के अनुरूप हों। तथापि प्राधिकार-पत्र धारक अग्रिम प्राधिकार पत्र के अंतर्गत आयातित माल की अप्रयुक्त मात्रा पर सीमा शुल्क प्राधिकारी को सीमा शुल्क कर लागू ब्याज सहित भुगतान करेगा। निर्यात दायित्व अवधि के बाद किए गए निर्यात पर नाशन प्रमाण पत्र देने से छूट के रूप में ही विचार किया जाएगा न कि लागू शुल्कों और ब्याज की देयता से छूट के रूप में।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:-

अग्रिम प्राधिकार पत्रों को मिलाने (क्लबिंग), निर्यात दायित्व अवधि का विस्तार और औषधि के आयात-पूर्व शर्त के साथ अपंजीकृत स्रोतों से आयात हेतु जारी किए गए प्राधिकार पत्रों में वास्तविक चूक के मामलों के नियमितीकरण से संबंधित प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 के अध्याय-4 में संशोधन किए गए हैं।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 18th October, 2017

No. 32/2015-2020

Sub: Amendments in Chapter-4 of Hand Book of Procedures 2015-2020, related to clubbing of Advance Authorisations, extension of Export Obligation period and regularisation of bonafide default in the cases where Authorisations were issued for import of drugs from unregistered sources with pre import condition-reg

F. No. 01/94/180/186/AM18/PC-4.—In exercise of powers conferred under Para 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade, in public interest, makes the following amendments in Hand Book of Procedures 2015-2020 as under:.

1) Para 4.38 of handbook of procedures 2015-20 is amended to read as under:**“4.38 Facility of Clubbing of Authorisations**

- (i) No clubbing of Authorisations issued on or before 31st March, 2009 shall be allowed.
- (ii) Request for clubbing shall be made in ANF - 4C to the concerned RA who has issued the Authorisations.
- (iii) Facility of clubbing of Advance Authorisations shall be available only for redemption/regularisation of such Authorisations and no further import or export shall be allowed.

- (iv) Facility of clubbing shall also be available for Advance Authorisations for Annual Requirement issued during Foreign Trade Policy period 2009-14 and 2015-20, wherever exports and imports have taken place as per Standard Input Output Norms (SION) notified.
- (v) Only Authorisations under which similar duty exemption has been availed shall only be allowed to be clubbed. Such Authorisations may pertain to different financial years.
- (vi) In case, exports are made outside EO period of any Authorisation, EO extension may be allowed before clubbing of such authorisation, as per Para 4.42 of Handbook of procedures on payment of composition fee.
- (vii) Only such Advance Authorisations shall be clubbed where exports under all Authorisations have been made within the initial/ extended EO period of the earliest issued Authorisation.
- (viii) Clubbing shall be permitted only when there is shortfall in fulfillment of export obligation occurred in first authorisation and excess exports are made in subsequent Authorisations. However, this condition may not be insisted when validity period (for import) of Authorisations runs concurrently and imports made in subsequent authorisation falls within validity period (for import) of first authorisation and such import made within validity period of first authorisation are on pro-rata, equal to or in excess to the extent of exports made in first authorisation. Subsequent Authorizations issued after expiry of validity of first Authorisation shall not be allowed to be clubbed.
- (ix) Clubbing of Authorisations issued with different EO periods shall also be allowed.
- (x) Accounting of exports made outside expiry of initial or extended EO period of earliest issued authorisation shall not be taken into consideration for EO fulfillment after clubbing of such Authorisations.
- (xi) Inputs which are common in all Authorisations shall only be clubbed and duty free inputs shall be accounted for as per SION/Ad-Hoc Norms fixed by NC. In other words all inputs covered in all Authorisations need not be same.
- (xii) Minimum value addition as prescribed in FTP and Procedures for the export product will be required to be maintained on clubbing. Upon clubbing, if shortfall in value or quantity is noticed, the same shall be regularized under the provisions of Para 4.49 of HBP 2015-20.
- (xiii) After clubbing, Authorisations shall for all purposes, be deemed to be one Authorisation. The value addition would be calculated on the basis of total CIF and total FOB arrived at after clubbing the Authorisations.
- (xiv) No clubbing shall be permitted in respect of Authorisations where misrepresentation / fraud have come to the notice of RA. Further, no clubbing of Authorisations, where EODC/redemption letter has already been issued or adjudication orders have already been passed by RA/Customs Authority, shall be permitted.
- (xv) **Additional provisions for clubbing of Authorisations covered under Appendix-30A (issued under FTP 2009-14)/Appendix-4J (issued under FTP 2015-20) and Authorisations issued with EOP less than 18 months:**
 - (a) Export obligation period of clubbed Authorisations shall be reckoned from the date of earliest import in any of the Authorisations proposed to be clubbed.
 - (b) Clubbing of such Authorisations shall be allowed provided all exports are completed within initial/extended Export Obligation period reckoned from date of earliest import in any of the Authorisations proposed to be clubbed.

2) Para 4.42 (d) is amended to read as under:

- (d) Extension in export obligation period for Authorisations issued under Appendix-4J (issued under FTP 2015-20) shall be allowed for a period not more than the half of the stipulated export obligation period. In such cases, composition fee shall be levied @ 0.5% per month of unfulfilled FOB value, in case exports effected are more than 50% within initial Export Obligation period and @ 1% per month where less than 50% exports have been effected within initial export obligation period.

3) Sub-Para (g) is inserted in Para 4.49:**(g) Regularization of Bonafide default in the cases where Authorisation was issued for import of drugs from unregistered sources with pre import condition:**

Import of drugs from unregistered sources issued with pre import condition shall be regularised in the following manner:

- (i) The Authorisation holder shall submit documents showing consumption of full imported quantity as per norms. In case, there is shortfall in fulfilment of EO and unutilised imported quantity remains with the authorisation holder, the Authorisation holder shall either submit a certificate from the jurisdictional Central Excise / Customs Authority certifying destruction of the unutilised imported quantity in their presence or proof of re-export of the same to the same supplier in-terms of para 4.43A of HBP 2015-2020.
- (ii) Exports made under free shipping bills/under same authorisation after expiry of EO period using unutilised quantity of drugs shall also be accepted in-lieu of submission of destruction certificate as stated in para (i) above, provided the exact description and technical characteristics of the drug exported matches with that of export item described in the Advance Authorisation. However, the Authorisation holder shall pay customs duty with applicable interest to the Customs Authority on unutilized quantity imported under Advance Authorisation. The exports made outside EO period shall only be considered for waiver of destruction certificate and not for waiver of liability of applicable duties and interest.

Effect of this Public Notice:

Amendments are made in Chapter-4 of Hand Book of Procedures 2015-2020, related to clubbing of Advance Authorisations, extension of Export Obligation period and regularisation of bonafide default in the cases where an Authorisation was issued for import of drugs from unregistered sources with pre import condition.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade